



अंग्रेजों की भारत विजय में सहायक पारिस्थितिक घटक- राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सन्दर्भ में

डॉ. रजत गंगवार,

असि. प्रोफेसर (इतिहास),

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीसलपुर, पीलीभीत, उ०प्र०

rajatgangwar4289@gmail.com

शोध सारांश

1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही मुगल सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया था परंतु बाद में उत्तराधिकार के लिए परस्पर संघर्षों ने उसे और अधिक धराशायी कर दिया। इसी समय नादिरशाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने उसे और जर्जर बना दिया। मुगलों का आधिपत्य कुछ ही क्षेत्र में शेष रह गया था। दिल्ली का मुगल दरबार षड्यंत्र का केंद्र बना हुआ था। खालसा भूमि में कटौती, जागीर संकट, आंकलित भू राजस्व प्राप्त न हो पाना आदि कारणों से न ही मुगल सैन्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण रख सके, न ही बढ़ते हुए अंग्रेजों के संकट की ओर देख सके। ऐसी विषम स्थिति में आगे चलकर मुगल अंग्रेजों का चाहते हुए भी कोई प्रतिरोध नहीं कर सके थे। यद्यपि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। जिस प्रकार अन्य यूरोपीय शक्तियों डच, पुर्तगाली, फ्रेंच आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य भारत से अत्यधिक धन कमाकर ब्रिटेन ले जाना था। परंतु जब उन्होंने देखा कि मुक्त एवं अवरोधक व्यापार के लिए राजनैतिक नियन्त्रण एवं राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेना अनिवार्य है और समकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति उनके अनुकूल थी, अतः उन्होंने राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न प्रारंभ कर दिए और वे भारत के भाग्य विधाता बन बैठे। प्रस्तुत शोधपत्र अंग्रेजों की भारत विजय में सहायक उन पारिस्थितिक



घटकों का विश्लेषण करता है जो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आयामों में विद्यमान थे। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारत आगमन से लेकर 1857 के विद्रोह तक, लगभग ढाई सौ वर्षों की अवधि में भारत धीरे-धीरे ब्रिटिश साम्राज्य की परिधि में आता गया। इस प्रक्रिया में भारत की आन्तरिक दुर्बलताएँ उतनी ही उत्तरदायी थीं जितनी अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा एवं संगठन-शक्ति। शोधपत्र में यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के उपरान्त उत्पन्न राजनीतिक शून्यता, मराठा, राजपूत, सिक्ख एवं अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता, जाति-व्यवस्था की कठोरता, धार्मिक विभाजन, आर्थिक संसाधनों का बाह्य-प्रवाह, और तकनीकी-सैन्य असमानता—ये सभी घटक सम्मिलित रूप से अंग्रेजी साम्राज्य-स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।

कुंजी शब्द - ईस्ट इंडिया कंपनी, स्थानीय शक्तियां, राष्ट्रीय चेतना, गुणवत्ता, राजनीतिक हित, सामुद्रिक नियंत्रण, व्यापारिक गतिविधियां, निज़ामत, संधि, दीवानी, संरक्षित रियासत, बफर स्टेट, सामरिक सुरक्षा, व्यपगत सिद्धांत, सहायक संधि, परस्पर वैमनस्यता, फूट डालो एवं राज करो, ब्रिटिश साम्राज्य

प्रस्तावना -भारत पर अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना इतिहास की सर्वाधिक जटिल एवं बहु-आयामी घटनाओं में से एक है। यह विजय केवल सैन्य बल द्वारा सम्भव नहीं हुई; वरन् इसमें भारत की आन्तरिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 1600 ई० में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को शाही चार्टर प्रदान किया, तब भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, किन्तु अगली शताब्दी में मुगल शक्ति के क्षरण के साथ-साथ जो राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हुई, उसने अंग्रेजों को वह अवसर प्रदान किया जिसकी वे तलाश में थे। इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार, "भारत की परिस्थितियों को समझे बिना ब्रिटिश विजय को नहीं समझा जा सकता।"



राजनीतिक सन्दर्भ में सहायक घटक

ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों में व्यापार करने की 15 वर्षों की अनुमति प्रदान कर दी। फलतः 1608 ईस्वी में हॉकिंस के नेतृत्व में एक व्यापारिक शिष्ट मण्डल भारत आया जिसने 1609 में सूरत में बसने की मुगल शासक जहांगीर से अनुमति मांगी परंतु पुर्तगाली एवं सूरत के व्यापारियों के विरोध के कारण उनकी मांग नामंजूर कर दी गई परंतु अंग्रेजों ने जब 1612 व 1614 में सूरत के नजदीक स्वाल्ली में पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को पराजित कर दिया। परिणामतः जहांगीर ने उन्हें दो कारणों- प्रथमतः अंग्रेजों की पुर्तगालियों की अपेक्षा नौसैनिक शक्ति अत्यधिक मजबूत सिद्ध हो चुकी थी। द्वितीय- देशी एवं विदेशी व्यापारियों के मध्य प्रतिद्वंद्विता से मुगलों को लाभ की आशा थी और इसके साथ ही व्यापारिक कर एवं चुंगी आदि से अतिरिक्त आय प्राप्ति की गुंजाइश थी, से सूरत में स्थाई व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल गई।

यद्यपि उभरती हुई स्थानीय शक्तियों में मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए और उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था। इसी के साथ कोलावा में उनका नौसैनिक बेड़ा भी था। यदि मराठे चाहते तो स्थानीय शक्तियों जाटों, राजपूतों एवं मुगलों से सहयोग करके अंग्रेजों को खदेड़ सकते थे और मुगलों के पतन से जो राजनीतिक शक्ति शून्यता आ गई थी, वह भी भर सकते थे परंतु मराठों के पास कोई भी निश्चित राष्ट्रीय विचारधारा एवं राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि उन्होंने अपनी आक्रामक नीति से राजपूतों, जाटों को अपना विरोधी बना लिया। आगे चलकर मराठा संघ स्वयं ही आंतरिक उलझनों एवं संघर्षों में लिप्त हो गया। उत्तराधिकार के प्रश्न पर पेशवा राघोबा अंग्रेजों से जा मिला। इस प्रकार मराठों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। उन्होंने मराठों की शक्ति को तहस-नहस कर दिया। अतः मराठे जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, नहीं निभा सके।



भारत विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्म, उपजातियों एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं में बंटा हुआ था क्योंकि भारत में ब्रिटेन की भांति औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास संभव नहीं हो सका था। ऐसी स्थिति में न तो धार्मिक, जातीय एवं रूढ़िगत संस्कारों में शिथिलता आ सकी और न ही भारत में वैज्ञानिक बोध एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना का विकास संभव हो सका। अतः भारत की एकता विभिन्न धार्मिक, सांप्रदायिक एवं जातीय गुटों में बंटी रही और वे एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते हुए कदमों का कोई प्रतिरोध नहीं कर सके बल्कि इस विश्रुंखलित सामाजिक व्यवस्था ने अंग्रेजी हुकूमत को अपने प्रसार के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया।

मुगलों एवं अन्य स्थानीय शक्तियों का सैन्य संगठन विभिन्न धार्मिक एवं जातीय एवं नस्ल के तत्वों के समीकरण से बना होने के कारण उसमें एकता एवं राष्ट्रीय चेतना का अभाव था जबकि अंग्रेजों का एक सुव्यवस्थित सैन्य संगठन था जो किसी भेदभाव के आधार पर संगठित नहीं था। ब्रिटेन में लोहे को गलाने की उच्च प्रौद्योगिकी विकसित होने से ढलवां बन्दूकों का एवं तोपों का विकास हो चुका था। यद्यपि बंदूकें एवं तोपें भारत के पास भी थीं। परंतु उच्च प्रौद्योगिकी के अभाव में इनमें उस गुणवत्ता का विकास संभव नहीं हो सका जो ब्रिटेन में हो चुका था। इसी के साथ भारतीय इन बंदूकों एवं तोपों को यूरोपीयों से ही खरीदते थे। अतः यूरोपीय अपने व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों को देखते हुए इन्हें उच्च कीमतों पर देते थे। ऐसी स्थिति में भारतीय ब्रिटिश कंपनी की सेना के समांतर सैन्य क्षमता पैदा नहीं कर सके। अतः ब्रिटिश कंपनी की सेना भारतीय पैदल एवं घुड़सवार सेना को बंदूकों एवं तोपों से पूरी तरह ध्वस्त एवं तहस-नहस कर देती थी।

इसी के साथ मुगलों तथा स्थानीय शक्तियों ने (मराठों को छोड़कर) नौसेना के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि अंग्रेजों का एक विकसित नौसैनिक तंत्र था तथा जल युद्धपोत होने के कारण समुद्री बेड़ों पर भी उसका आधिपत्य था। अतः जब अंग्रेज पराजय की स्थिति में होते थे तो वह समुद्री टापू पर



शरण ले लेते थे। उदाहरणार्थ जब 1686 में अंग्रेजों पर औरंगजेब की मुगल सेना ने आक्रमण किया तो उन्होंने गंगा के मुहाने पर एक ज्वार ग्रस्त टापू पर शरण ले ली। यदि मुगलों के पास नौसैनिक शक्ति होती तो उन्हें पराजित किया जा सकता था। सामुद्रिक नियंत्रण स्थापित हो जाने से व्यापारिक गतिविधियों पर भी इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। अतः जब कोई स्थानीय शक्ति, मुगल या महाजन एवं व्यापारी अंग्रेजी नीतियों की अवहेलना करते थे तो वे व्यापारिक मार्गों को अवरूद्ध करके आर्थिक हानि पहुंचा देते थे। अतः मुगलों, स्थानीय शक्तियों, महाजनों एवं व्यापारियों ने चाहते हुए भी अंग्रेजी नीतियों का प्रतिरोध नहीं कर पाते थे।

अंग्रेजों की राजनीतिक विजय का इतिहास बंगाल की विजय से प्रारंभ होता है। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल राज्य की स्थापना की थी। अंग्रेज बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण कायम करने का अवसर ढूंढ रहे थे। उसी समय जब अली वर्दी खान ने अपने पुत्र न होने की स्थिति में अपने धवते सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो अंग्रेजों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया और सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध ढाका की घसीटी बेगम, पूर्णिया के शौकत जंग को उकसाकर सिराजुद्दौला का विरोधी बना दिया। बाद में सेनापति मीरजाफर को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद बंगाल के सेठ अमीरचंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ को भी लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित करके बंगाल को अपने अधीन किया। मीरजाफर को बंगाल का नवाब बनाकर द्वैध शासन कायम कर दिया। दीवानी, राजस्व वसूलने एवं उससे संबंधित न्यायिक मामले अपने पास रखे तथा निजामत, लोक शांति व्यवस्था एवं फौजदारी मामले बंगाल के नवाब के अधीन थे। अतः उत्तरदायित्व का दायित्व बंगाल के नवाब के ऊपर थोप दिया तथा नियंत्रण अपने पास रखा। इसी के साथ ब्रिटिश रेजीमेंट को भी रखा गया जो बंगाल के नवाब की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था। बंगाल विजय से अब प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ-साथ आर्थिक



दोहन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी आर्थिक दोहन से वे व्यापारिक गतिशीलता बनाए रखने में कायम हो सके। साथ ही साथ सैन्य तंत्र को मजबूत करने में भी सफल हो सके।

बक्सर के युद्ध के बाद जब मीर कासिम ने भागकर अवध के नवाब के यहाँ शरण ली तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम तथा मीर कासिम ने संयुक्त मोर्चा बनाकर ब्रिटिश कंपनी से युद्ध किया परंतु 1764 में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना ने इस संयुक्त मोर्चे को पराजित किया और वे भारत के भाग्य विधाता बन बैठे। युद्ध में पराजित होने के बाद मुगल शासक शाह आलम की अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि हुई जिसमें इलाहाबाद एवं कड़ा जिला तथा 50 लाख रुपया शाह आलम को अवध के नवाब से लेकर दे दिए गए। बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। अवध को नवाब के अधीन ही रखकर संरक्षित रियासत घोषित कर दिया गया। बंगाल में पुनः मीरजाफर को नाम-मात्र का शासक बना दिया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित हो जाने से अंग्रेज कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को और आगे चलकर हैदराबाद के नवाब हैदर अली एवं टीपू को पराजित करने में सफल हो सके। दूसरी ओर अवध को सुरक्षित रियासत बना देने से मराठों एवं अपने मध्य बफर स्टेट यानी मध्यवर्ती राज्य बनाने में सफल हो सके जिससे वे प्रत्यक्ष रूप से मराठों से संघर्ष से बच सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर मराठों पर नियंत्रण भी रख सकते थे। अवध के नियंत्रण ने मराठों पर ही नियंत्रण एवं सामरिक सुरक्षा प्रदान नहीं की बल्कि अफगानों एवं रुहेला युद्धों में इन्हें विजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

अंग्रेजों का बंगाल एवं गंगा घाटी के मैदानी भागों पर आधिपत्य स्थापित होने के बाद प्रमुख रूप से लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यपगत सिद्धांत एवं लॉर्ड बेल्लेजली ने सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अनुसार जो रियासतें अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गईं, उन्हें दत्तक पुत्र लेने का अधिकार नहीं होगा और उनकी रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर ली जाएं और जो रियासतें ब्रिटिश कंपनी के अधीन हैं, उन्हें दत्तक पुत्र लेने का अधिकार था परंतु ब्रिटिश कंपनी की अनुमति



आवश्यक रखी गई। अतः उसने व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर सातारा 1848 में, जैतपुर-संबलपुर 1849 में, भरतपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में विलय कर लिया। कुर्ग एवं कर्नाटक को कल्पित विश्वासघात का आरोप लगाकर, अवध एवं बरार को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया।

लॉर्ड बेल्लेजली ने सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके अनुसार सहायक संधि में आने वाली रियासतें ब्रिटिश फौजी टुकड़ी रखती थीं, जिनका समस्त खर्च वे स्वयं उठाते थे। सामरिक एवं परराष्ट्रनीति का निर्धारण ब्रिटिश कंपनी करती थी तथा एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखने का भी प्रावधान था, जो रियासत की गतिविधियों पर नजर रखता था। अतः इस सहायक संधि के माध्यम से सेना का आर्थिक बोझ कम हो गया। साथ ही इन रियासतों पर इनका सैन्य नियंत्रण भी हो गया। परराष्ट्रनीति अंग्रेजों के हाथों में आने से ये रियासतें अन्य शक्तियों से ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की संधि नहीं कर सकती थीं। ब्रिटिश प्रतिनिधि से उनकी आन्तरिक गतिविधियों की सारी जानकारी ब्रिटिश कम्पनी को आसानी से मिलती रहती थी। जब ब्रिटिश कंपनी का स्थानीय एवं अन्य शक्तियों से संघर्ष या युद्ध होता था तो ये रियासतें भी भाग लेती थीं।

अतः स्थानीय शक्तियों में परस्पर वैमनस्यता की वृद्धि होती चली गई। धन एवं जन की हानि का उत्तरदायित्व भी इन देसी रियासतों पर ही होता था। सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेज अपनी “फूट डालो एवं राज करो” की नीति में भी आसानी से सफल हो सके। सहायक संधि के माध्यम से ही वेल्लेजली हैदराबाद के नवाब, अवध के नवाब एवं मराठों की शक्ति को तहस-नहस करके ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने में सफल सिद्ध हुए।



सामाजिक सन्दर्भ में सहायक घटक

भारतीय समाज की जाति-व्यवस्था अंग्रेजों की विजय में एक महत्वपूर्ण सहायक घटक सिद्ध हुई। जाति के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों में गहरी दरारें थीं। उच्च जातियों और निम्न जातियों के बीच की खाई इतनी गहरी थी कि वे एकसाथ किसी सामान्य शत्रु के विरुद्ध नहीं लड़ सकते थे। इसी विभाजन का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने अपनी सेना में विभिन्न जातियों एवं क्षेत्रों के सिपाहियों को शामिल किया और उनके बीच प्रतिस्पर्धा एवं अविश्वास को बनाए रखा।

इतिहासकार एम०एन० श्रीनिवास के अनुसार, "जाति-व्यवस्था ने भारत में सामाजिक एकता की सम्भावना को सीमित कर दिया था। विभिन्न जातियों के लोगों में जो आपसी अविश्वास था, वह अंग्रेजों की 'फूट डालो' नीति का सबसे बड़ा सहायक था। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों ने हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों में विष घोल दिया था। मराठाओं और मुगलों के बीच का संघर्ष मूलतः राजनीतिक था, किन्तु धार्मिक रंग चढ़ने से यह और अधिक तीखा हो गया। अंग्रेजों ने इस धार्मिक विभाजन को बड़ी चतुराई से अपने पक्ष में भुनाया।

1857 के विद्रोह से पूर्व तक भारत में कभी भी हिन्दू और मुसलमान एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित नहीं हो सके। यद्यपि 1857 के विद्रोह में दोनों समुदायों ने कुछ समय के लिए मिलकर संघर्ष किया, किन्तु यह सहयोग अल्पकालिक सिद्ध हुआ 18वीं शताब्दी तक भारत की पारम्परिक शिक्षा प्रणाली—मदरसे और पाठशालाएँ—मुख्यतः धार्मिक एवं साहित्यिक ज्ञान तक सीमित थी। आधुनिक विज्ञान, तकनीक, व्यापार एवं राजनीतिशास्त्र की शिक्षा का सर्वथा अभाव था। इसके विपरीत, यूरोप में वैज्ञानिक क्रान्ति के बाद से शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदल गया था। इस बौद्धिक अन्तर ने अंग्रेजों को तकनीकी एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में स्पष्ट श्रेष्ठता प्रदान की।

भारत में 'राष्ट्र' की अवधारणा 18वीं शताब्दी में लगभग अनुपस्थित थी। लोगों की पहचान उनकी जाति, उनके धर्म, उनके गाँव या उनके राजा से थी—न कि किसी एकीकृत राष्ट्रीय पहचान से। इस कारण से जब अंग्रेज किसी एक राज्य पर अधिकार करते थे, तो अन्य राज्यों के लोग प्रायः उदासीन रहते थे। बंगाल की विजय ने दक्कन के शासकों को चेताया नहीं, और दक्कन की पराजय ने पंजाब को नहीं। यह भावना, जिसे इतिहासकार बी०जी० तिलक और बाद में गाँधीजी ने 'राष्ट्रीय चेतना का अभाव' कहा, ब्रिटिश विजय की सबसे बड़ी सहायक शर्त बनी अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीय सिपाहियों को बड़ी संख्या में शामिल किया। 1857 तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या यूरोपीय सैनिकों से पाँच-छह गुना अधिक थी। इन्हीं भारतीय सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों ने भारत के अन्य भागों को जीता। यह सामाजिक विभाजन का ही एक पहलू था—एक क्षेत्र के भारतीय दूसरे क्षेत्र के भारतीयों के विरुद्ध लड़ रहे थे।

आर्थिक सन्दर्भ में सहायक घटक

17वीं-18वीं शताब्दी में भारत विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक था। अंग्रेज अर्थशास्त्री अंगस मैडिसन के अनुमान के अनुसार, 1700 ई० में भारत की विश्व GDP में हिस्सेदारी लगभग 24.4% थी। भारत के मसाले, कपड़े, हीरे-जवाहरात और अन्य उत्पाद यूरोपीय बाजारों में अत्यन्त लोकप्रिय थे। यही आर्थिक आकर्षण था जिसने अंग्रेजों को भारत की ओर खींचा। 18वीं शताब्दी तक भारत की हस्तशिल्प और कपड़ा-उद्योग विश्वस्तरीय थी। ढाका की मलमल, बनारस का रेशम, और सूरत का कपड़ा विश्वभर में प्रसिद्ध था। किन्तु अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ ब्रिटिश निर्मित वस्त्र (जो औद्योगिक क्रान्ति के बाद सस्ते हो गए थे) भारत में बाढ़ की तरह आने लगे। इसके साथ ही कम्पनी ने भारतीय वस्त्रों के ब्रिटेन-निर्यात पर भारी कर लगाए। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक 'Poverty and Un-British Rule in India' में इस व्यापारिक असमानता का विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने सिद्ध किया कि किस प्रकार ब्रिटिश व्यापार नीतियों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को एकपक्षीय बना दिया। उत्पल पटनायक एवं



मार्टिन लोबे के नवीनतम शोध के अनुसार, 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत से लगभग 45 खरब डॉलर का धन निकाला।

अंग्रेजों ने भारत में भूमि-राजस्व व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 1793 में लागू की गई स्थायी बन्दोबस्त ने बंगाल में जमींदारों को भू-स्वामी बना दिया और किसानों को उनकी दया पर छोड़ दिया। 1820 में मद्रास में रयोटवाड़ी प्रणाली और उत्तर भारत में महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई। इन सभी व्यवस्थाओं में एक बात समान थी—भारी कर-भार। रेलव के अनुसार, 19वीं शताब्दी में भारतीय किसानों पर लगाया गया राजस्व प्रायः उनकी कुल उपज का 50-70% तक होता था। इस भारी कर-बोझ ने किसानों को साहूकारों के चंगुल में धकेल दिया और कृषि-क्षेत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बार-बार पड़ने वाले अकाल (1770 का महाकाल जिसमें बंगाल की एक-तिहाई जनसंख्या मारी गई) इसी आर्थिक शोषण के परिणाम थे।

18वीं शताब्दी की ब्रिटिश औद्योगिक क्रान्ति ने यूरोप को तकनीकी दृष्टि से सम्पूर्ण एशिया से बहुत आगे कर दिया। भाप के इंजन, बेहतर तोपखाना, आधुनिक नौसेना और रेलवे—ये सब ब्रिटिश शक्ति के स्तम्भ थे। इसके विपरीत, भारतीय राज्यों के पास पारम्परिक हथियार और पुरानी युद्ध-पद्धतियाँ थीं। यह तकनीकी अन्तर सैन्य एवं आर्थिक दोनों क्षेत्रों में निर्णायक सिद्ध हुआ। रेलवे और टेलीग्राफ के माध्यम से अंग्रेज तेजी से सेना एवं सूचना का संचालन कर सकते थे, जबकि भारतीय राज्यों को इसमें कई गुना अधिक समय लगता था। यह सूचना-असमानता भी अंग्रेजों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण घटक थी

निष्कर्ष-

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अंग्रेजों की भारत-विजय किसी एकल कारण का परिणाम नहीं थी, वरन् राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयामों में व्याप्त अनेक परस्पर-संबद्ध घटकों का समवेत



प्रभाव थी। मुगल साम्राज्य के पतन से उत्पन्न राजनीतिक शून्यता, क्षेत्रीय शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता, जाति-धर्म पर आधारित सामाजिक विभाजन, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, और आर्थिक शोषण की व्यवस्था—ये सब मिलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते थे जिसमें एक संगठित, तकनीकी रूप से उन्नत और कूटनीतिक दृष्टि से चतुर शक्ति के लिए भारत पर आधिपत्य स्थापित करना अपेक्षाकृत सरल हो गया। रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत की पराजय केवल राजनीतिक नहीं थी, यह सांस्कृतिक और मानसिक भी थी। इस सन्दर्भ में, भारत की विजय का वास्तविक अर्थ यही है कि भारतीय समाज ने अपनी आन्तरिक चुनौतियों से उबरने में असमर्थता दिखाई और यही असमर्थता ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सबसे बड़ी सहायक बनी। 1857 का विद्रोह, यद्यपि असफल रहा, किन्तु इसने पहली बार यह सिद्ध किया कि जब भारतीय एकजुट होते हैं तो विदेशी शासन को चुनौती दी जा सकती है। यह चेतना आगे चलकर भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम की आधारशिला बनी।

संदर्भ-

1. चंद्र, बिपिन, आधुनिक भारत: ओरिएंट ब्लैक्सवान प्रकाशन, नई दिल्ली, 2025
2. मजूमदार, आर०सी०, रायचौधरी, एच०सी० और दत्ता, के०के०, एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया: ट्रिनिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2023
3. मुखर्जी, आर०के०, द राइज एंड फॉल ऑफ़ द ईस्ट इंडिया कंपनी: पॉपुलर प्रकाशन, मुंबई, 1955
4. बंधोपाध्याय, शेखर, प्लासी से विभाजन तक: ओरिएंट ब्लैक्सवान प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007
5. शुक्ला, राम लखन, आधुनिक भारत का इतिहास: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2015
6. सुंदरलाल, भारत में अंग्रेजी राज, भाग 2: ओंकार प्रेस, इलाहाबाद, 1918
7. सरकार, सुमित, आधुनिक भारत: राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009



8. ग़ोवर, यशपाल, आधुनिक भारत का राजनीतिक इतिहास: एस०चंद प्रकाशन, नई दिल्ली, 2020
9. ताराचंद, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
10. शर्मा, रामशरण, भारतीय इतिहास की समझ: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2001
11. त्रिपाठी, अमलेश, भारत में राष्ट्रवाद का उदय: हिन्दुस्तानी अकादमी. इलाहाबाद, 1998
12. मिश्र, शिवकुमार, आधुनिक भारत का इतिहास: लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2003
13. गुप्त, जे०पी०, भारत में ब्रिटिश राज: आर्थिक शोषण और सामाजिक प्रभाव : प्रभात प्रकाशन. नई दिल्ली, 2005
14. नेहरू, जे०, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया: साइनेट प्रेस, कलकत्ता, 1946